गैंगस्टर्स से मिलने वाली धमकियों का मामला विधानसभा में गूंजा

निर्दलीय विधायक रविन्द्र भाटी ने सदन में कहा ''राजस्थान में किसी की परचून की दुकान भी ढंग से चल रही है तो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स व जेल में बैठे बदमाश धमकियां देते हैं।''

- भाटी ने कहा कि ''उत्तरप्रदेश-बिहार और मुंबई की तर्ज पर राजस्थान में भी गैंगस्टर्स को ठोकने की आवश्यकता है। एक को ठोक देंगे तो बाकियों में मैसेज जाएगा।''
- गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस को सदन में घेरते हुए कहा कि, ''हम गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस राज में तो बदमाश छाती पर चढ़कर गोली मारते थे।''
- मंत्री बेढ़म की इस टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत विपक्षी विधायकों ने आपत्ति जताई

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। गैंगस्टर्स से व्यापारियों व आमजन को लगातार मिल रही धमकियों का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजा। निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि, आज विदेश में बैठे गैंगस्टर्स और जेल में बैठे बदमाश लोगों को धमकाकर रंगदारी मांग रहे हैं। हमें उत्तरप्रदेश-बिहार और मुंबई की तर्ज पर गैंगस्टर्स को ठोकने की आवश्यकता है। एक को ठोक देंगे तो बाकियों में मैसेज जाएगा। इस मुद्दे पर गृह राज्यमंत्री ने जवाब देते हुए कांग्रेस राज को कोसा तो सदन में हंगामा मच गया।

शून्यकाल में निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह सिंह भाटी ने कहा कि इंटरनेट कॉलिंग से व्यापारियों, डॉक्टरों सहित प्रतिष्ठित लोगों को वसूली के लिए गैंगस्टर्स की धमकी आम बात हो गई है। अब तो हालात ऐसे हैं कि अगर किसी की परचून की दुकान भी ढंग से चल रही है तो उसको भी धमकी मिल रही है। इन धमकियों से व्यापारियों में दहशत है। जिसको धमकी मिलती है, वह अपनी दुकान, अपने शोरूम, अपने प्रतिष्ठान तक नहीं जा पाता। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। परिवार घरों में कैद होकर रह जाता है।

भाटी ने कहा कि, जिसे धमकी मिलती है, उसके घर के बाहर 2 पुलिसकर्मी तैनात कर देते हैं। उसके बाद भी गैंगस्टर फोन करके कहते हैं कि ये दो पुलिसवाले क्या आपको बचा लेंगे? यह जानकारी इन गैंगस्टर्स तक कौन पहुंचाता है? कोई स्थानीय नेटवर्क है, जो इनकी मदद करता है।

भाटी ने कहा कि, संगठित अपराध में मदद करने वाले स्थानीय गैंग की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त कर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। रक्तरंजित राजस्थान होने से बचाना है तो चुन-चुन कर बदमाशों को बाहर निकालकर कार्रवाई करने की जरूरत है। नाबालिग बच्चों तक को क्राइम में शामिल किया जा रहा है। हमें यूपी-बिहार, मुंबई की तर्ज पर गैंगस्टर्स को ठोंकने की आवश्यकता है। एक को ठोंक देंगे तो बाकी बदमाशों में मैसेज जाएगा।

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि, एजीटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग के 50 हजार के इनामी अमरजीत बिश्नोई और उसकी पत्नी सुधा कंवर को इटली से तथा आदित्य जैन ऑफ टोनी को दुबई से गिरफ्तार करवाया।

अमित शर्मा को सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अमेरिकी एजेंसियों को सूचित कर अमेरिका में डिटेन करवाया। हम अपराधियों के खिलाफ ताकत से कार्रवाई करेंगे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बेढ़म ने कहा कि, हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। एजीटीएफ ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ 2024 में 36484 टीमों का गठन कर 1 लाख 23 हजार से ज्यादा स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की है। कांग्रेस के राज में तो आपकी छाती पर चढ़कर अपराधी गोली चलाते थे, आप अपराधियों के जवाब में कुछ करते नहीं थे, अधिकारियों को और काम नहीं करने देते थे।

गृह राज्य मंत्री की इस टिप्पणी और तंज से सदन में हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि, आप पिछला छोड़िए, आप क्या कर रहे हो, गैंगस्टर्स और अपराध पर क्या कार्रवाई की, उस पर बताइए। इस दौरान दोनों ओर से तनातनी होने लगी। बेढ़म ने कहा कि जवाब पूछा है तो अब सुनना होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि 100 फीसदी रोक लगा दी, लेकिन पिछली सरकार के वक्त में जिस तरह का जंगल राज था, हर दूसरे दिन व्यापारियों को धमकाना, अपहरण की घटनाएं, फायरिंग की घटनाएं होती थी, उन पर अंकुश लगाया है।

कांग्रेस विधायक को स्पीकर देवनानी की कड़ी चेतावनी

जयपुर (विसं)। गैंगस्टर्स द्वारा रंगदारी वसूले जाने के मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस-बीजेपी के बीच खूब आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला।

कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने 23 फरवरी को गैंगस्टर्स के रंगदारी वसूलने के मामले में स्थगन प्रस्ताव लगाया था, लेकिन सदन में इसे उठाया नहीं। इसे लेकर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में कहा कि स्थगन प्रस्ताव लगाकर सदन में ही रहे। एक विधायक कल स्थगन प्रस्ताव लगाकर सदन से चले गए, जबकि जिस वक्त स्थगन प्रस्ताव के लिए व्यवस्था दी, तब वे मौजूद थे, लेकिन बोलने की बारी, तब सदन से चले गए, आगे से ऐसा नहीं हो।इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रंगदारी मामले में स्पीकर से सदन में चर्चा रखवाने की मांग की। इस पर स्पीकर ने अलग से आधे घंटे की चर्चा का आश्वासन दिया। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देने की परंपरा नहीं है, लेकिन मुद्दा ही इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति भी वो कर रहे हैं, जिनका विधायक इसी मुद्दे पर स्थगन लगाकर मैदान छोड़कर भाग गया।

'बजट सत्र में ढिलाई नहीं चलेगी'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को दिए कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा की 'हां पक्ष' लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई।

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मंगलवार को विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। बैठक में अब तक के सत्र के दौरान मंत्रियों के प्रदर्शन, प्रश्नकाल में जवाब देने की तैयारी और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति पर विस्तार से मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने विधायकों की अनुपस्थिति और कुछ मंत्रियों के अधूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचने पर नाराजगी जताई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कहा कि बजट सत्र सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसमें सभी विधायकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नियमित रूप से सदन में उपस्थित रहने वाले विधायकों की सराहना करते हुए उनके लिए तालियां भी बजवाईं। इनमें श्रीचंद कृपलानी, जोगेश्वर गर्ग, सुभाष मील, संजीव बेनीवाल, कल्पना राजे और अर्जुन लाल जीनगर के नाम शामिल रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने 2 वर्षों में हर विभाग में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें तथ्यों और आंकड़ों के साथ मजबूती से सदन में रखा जाना चाहिए। उन्होंने माना कि पिछले कुछ दिनों में प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्री अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे, जिससे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला। सीएम ने मंत्रियों को आक्रामक और आत्मविश्वासपूर्ण रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रश्नों के उत्तर पूरी तैयारी, समन्वय और प्रामाणिक आंकड़ों के साथ दिए जाएं। विभागीय समन्वय की कमी दूर करने और तैयारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार मुद्दों को उछालकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में सभी मंत्रियों और विधायकों को एकजुट होकर प्रभावी ढंग से जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी इस समय अंतर्कलह से गुजर रही है, जबकि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जनता सरकार के काम से संतुष्ट है। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि बजट सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी सदस्यों को नियमित उपस्थिति व ठोस तैयारी सुनिश्चित करनी होगी।

सभी पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का आश्वासन

जयपुर (विसं)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी पात्र आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए एवं वंचित पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी 2025 से खोल दिया गया है।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामस्वरूप लाम्बा के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 4,46,61,960 की सीलिंग सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त स्थानों के विरुद्ध पात्र वंचित लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने की कार्यवाही जारी है।

मंत्री ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खुलने के बाद विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में 12 फरवरी 2026 तक ब्लॉक एवं नगरपालिका स्तर पर कुल 3,457 आवेदन प्राप्त हुए।

मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स से प्रदेश के 61 लाख पशुओं का नि:शुल्क इलाज

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में दिया जवाब

जयपुर (विसं)। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशुओं के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी, 2024 से प्रारंभ इस योजना के तहत 15 फरवरी, 2026 तक मोबाइल वेटरनरी यूनिट द्वारा ऑन-कॉल सेवाओं एवं शिविरों के माध्यम से 15 लाख 99 हजार 840 पशुपालकों के कुल 61 लाख 30 हजार 856 पशुओं का नि:शुल्क उपचार किया गया है।

उन्होंने बताया कि चूरू जिले में 35 हजार 466 पशुपालकों के 1 लाख 23 हजार 374 पशुओं का उपचार किया गया, जबकि चूरू विधानसभा क्षेत्र में 7 हजार 666 पशुपालकों के 36 हजार 549 पशुओं का निशुल्क इलाज किया गया।

उन्होंने बताया कि योजना प्रारंभ होने (24 फरवरी 2024) के समय विभाग का कॉल सेंटर शुरू नहीं हो पाने के कारण विभाग द्वारा गांव-गांव में शिविर आयोजित कर पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।

इन शिविरों में इलाज किये गए पशुओं की संख्या भी इन आंकड़ों में शामिल है। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर, 2024 को विभाग का कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया तथा 31 दिसंबर, 2024 से यूनिट द्वारा पशुओं का ऑन-कॉल नि:शुल्क उपचार नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हरलाल सहारण द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना की सफलता एवं प्रदेश की विशाल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय पशुपालन मंत्री से प्रदेश में मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

कुमावत ने बताया कि यह योजना केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स संचालित हैं। इन मोबाइल वाहनों की शत-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जबकि इनके संचालन के लिए बजट व्यवस्था 60 प्रतिशत केंद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

देशभर में विरोध दिवस मनाएगा भारतीय मजदूर संघ

जयपुर । भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) 25 फरवरी को देशव्यापी विरोध दिवस मनाएगा। पुरी में आयोजित संगठन के 21 वें अखिल भारतीय अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार बीएमएस की सभी इकाइयों जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकारों से श्रमिकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग करेंगी।

बीएमएस के प्रचार मंत्री अक्षय कुमार मीणा ने बताया कि श्रमिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे समय-समय पर सरकार के सामने रखे गए, लेकिन अब तक अपेक्षित सकारात्मक और ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि देशभर में लाखों मिड-डे मील और आशा कार्यकर्ता बहुत कम मानदेय पर काम कर रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग पाँच दशकों की सेवा के बावजूद 'योजना कर्मी' का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि उनसे प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक कार्य लिया जा रहा है और लगातार नई जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं।

एसीबी ने बीते 3 माह में 149 आरोपी गिरफ्तार किए

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। पिछली तिमाही में ब्यूरो ने कई बड़े मामलों का खुलासा करते हुए बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए कई प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में व्यापक जांच और ट्रैप कार्रवाई की गई।

आंकड़ों के अनुसार पिछली तिमाही में एसीबी ने कुल 111 प्रकरण दर्ज कर 149 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 68 ट्रैप कार्रवाई, 19 रिश्वत मांग के मामले, 8 आय से अधिक संपत्ति और 16 पद के दुरुपयोग से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।

एसीबी महानिदेशक के अनुसार 8 जनवरी 2026 को परिवहन विभाग से जुड़े प्रकरण में अधिकारियों-कर्मचारियों और निजी दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक तलाशी ली गई।

9 जनवरी को झालावाड़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल को 84 हजार रुपये कीमत का आईफोन रिश्वत में लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

13 फरवरी को पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की गई, जिसमें भारी नकदी, जेवरात और अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ।16 फरवरी को नगर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र सिंह को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह राशि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा और डॉ. राकेश कलोरिया के लिए ली जा रही थी। इसके अलावा 17 फरवरी को जल जीवन मिशन मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। एसीबी ने इससे पहले 20 दिसंबर 2025 को अजमेर इकाई की कार्रवाई में हरियाणा के सिरसा साइबर क्राइम थाने के उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों को छह लाख रुपये की संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ पकड़ा था। वहीं 15 दिसंबर 2025 को भीलवाड़ा में एक मेडिकल अधिकारी को 11 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। एसीबी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है।

ई.एस.आई.सी. अस्पताल में विशेष सेवा पखवाड़ा शुरू

जयपुर (कासं)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के 75वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर में सांसद मंजू शर्म ने 'विशेष सेवा पखवाड़ा' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैंसर रोग संबंधी विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर भी शुरु किया गया। सांसद मंजू शर्मा ने बीमाकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रिछपाल मीना ने बताया कि अस्पताल के विभिन्न विभागों द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारजनों को त्वरित एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। जटिल रोगों के निदान एवं उपचार के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डीन राजेश चेटीवाल ने सांसद से चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद मंजू शर्मा ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया गया।

देवस्थान विभाग का कोई मंदिर बीते 2 वर्षों में बंद नहीं : कुमावत

जयपुर (विसं)। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि देवस्थान विभाग द्वारा 938 मंदिरों को प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है। ये सभी राजकीय मंदिर एवं देवालय आमजन के दर्शनों के लिए खुले हैं, गत 2 वर्ष से कोई मंदिर बंद नहीं है। देवस्थान मंत्री कुमावत प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्रीचन्द कृपलानी द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के मांडल में स्थित देवनारायण मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन नहीं है। मंदिर को रिसीवरी में लेने के बाद यहां सुरक्षा की दृष्टि से दीवार ऊंची कर गेट पर ताला लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक वाद भीलवाड़ा के न्यायालय में लंबित है, जिसकी प्रथम सुनवाई 16 मई 2024 को हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी। इस प्रकरण में अब तक 16 बार सुनवाई हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में राज्य सरकार कोर्ट के निर्णय की पालना करेगी।

मंत्री कुमावत ने बताया कि देवस्थान विभाग के अंतर्गत राजकीय प्रत्यक्ष श्रेणी के 390, आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 तथा सुपुर्द श्रेणी के 343 मंदिर हैं। इसी प्रकार मंदिर मंडल अधिनियम के अंतर्गत, टेंपल बोर्ड के 2 मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों का नियंत्रण, व्यवस्था, जिर्णोद्धार आदि कार्य विभाग द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अन्य मंदिरों में यह कार्य संस्थाओं, ट्रस्ट अथवा स्थानीय निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं।

इससे पहले विधायक कृपलानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में देवस्थान मंत्री ने बताया कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित ऐसे कोई भी राजकीय मंदिर तथा देवालय नहीं है जो 2 वर्ष से अधिक समय से आमजन के दर्शनों के लिए नहीं खोले गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित कोई भी राजकीय मंदिर/देवालय बंद नहीं है। मंत्री कुमावत ने कहा कि देवस्थान विभाग के अधीन राजकीय मंदिर आमजन के लिए सदैव दर्शनों के लिए निर्धारित समय अनुसार खुले रहते हैं।

'मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान में जल संरक्षण के कार्यों को मिली नई गति'

जिले और शहरी स्थानीय निकाय जल संचयन को दें प्राथमिकता : केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री

- वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का द्वितीय चरण प्रदेश में होगा 25 मई से शुरू : मुख्यमंत्री
- रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण, मरम्मत कार्यों को दें गति : भजनलाल शर्मा

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने मंगलवार को नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से इस बैठक में वर्चुअली जुड़े।

जयपुर (कासं)। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत बारिश के पानी की पर्याप्त रिचार्ज कैपेसिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से पानी बचाने के कामों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री मंगलवार को नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जन सहभागिता के माध्यम से नदी का जल संरक्षण अनुकरणीय पहल है।

रामजल सेतु योजना राजस्थान के लिए वरदान

पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर गांव, हर खेत में वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजने के संकल्प से प्रेरित होकर राज्य सरकार प्रदेश को जल संपन्न बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।रामजल सेतुलिंक परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए यमुना जल समझौते की डीपीआर का कार्य भी अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली बैठक में जुड़े। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 में शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसाइटीज और आम जन की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के अर्न्तगत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और मरम्मत कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करते हुए सभी जिले निर्धारित समय में लक्ष्यों की प्राप्ति करें।

जल संचय जन भागीदारी अभियान बना जन-आंदोलन

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य के क्रम में प्रारंभ किया गया जल संचय जन भागीदारी अभियान एक जन-आंदोलन बन चुका है। इस अभियान से वर्षा के एक-एक बूंद जल को सहेजा जा रहा है।उन्होंने कहा कि राजस्थान ने अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अभियान के प्रथम चरण(1.0) में हमारा प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। बाड़मेर एवं भीलवाड़ा जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्हें केंद्र सरकार ने सराहा और पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा किपानी की महत्ता को राजस्थान से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। इसी क्रम मेंराज्य सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी पहल कर प्रदेशभर में भूजल स्तर में सुधार लाने के साथ ही पारम्परिक जल स्त्रोतों को नया जीवन देने का प्रयास किया है। इन अभियानों के माध्यम से प्रदेशभर में जनचेतना आई है, जिसके आगामी समय में सुखद परिणाम सामने आयेंगे।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के द्वितीय चरण की शुरूआत गंगा दशहरा (25 मई) को शुरू करने जा रही है। जो 5 जून को पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा। इस अवसर पर डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर्स ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अर्न्तगत किये गए प्रगतिरत कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोरा, नेशनल वाटर मिशन की अतिरिक्त सचिव मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी सहित जिला कलेक्टर्स, नगर निकाय आयुक्त वीसी के माध्यम से जुड़े।

सनातनियों को तीर्थराज पुष्कर जाना चाहिए : बालमुकुंदाचार्य

जयपुर (विसं)। विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सबकी अपनी-अपनी आस्था और अपना-अपना विश्वास है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमें किसी के विश्वास और आस्था में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। मैं सनातनी हूँ और कहना चाहूंगा कि अजमेर जाएं तो तीर्थराज पुष्कर में स्नान जरूर करें, ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन करें तथा पुण्य कमाएं। उन्होंने कहा कि सनातनियों को समझने की आवश्यकता है, और पृथ्वीराज चौहान को स्मरण करने की आवश्यकता है इतिहास को पढ़ने और जानने की आवश्यकता है और वह स्थान कैसे बना और किनका है यह भी समझने की आवश्यकता है। मेरे इस पूरे वक्तव्य का अगर कोई अध्ययन करेगा तो वह स्वयं ही अपने आप पुष्कर जाना ज्यादा अच्छा समझेगा और सनातनियों के लिए तो तीर्थराज पुष्कर विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के मित्रों को सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक, धर्म और राम की चर्चा करने वालों से उनको हमेशा आपत्ति रही है, इसमें धर्म गुरुओं को आपत्तिजनक शब्दों में बोलना, राम को काल्पनिक बताना और जब भी अध्यात्म की, सनातन की भारत की संस्कृति की बात आएगी तो कांग्रेस का छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वह हमेशा उसके खिलाफ खड़ा रहेगा यह कांग्रेस की रीति नीति है और कांग्रेस का यह स्वभाव है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी उन्होंने पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इसे व्यक्तिगत विषय बताया।